



राजपत्र हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, ६ अप्रैल, १९९६/१७ चैत्र, १९१८

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-२, ३० दिसम्बर, १९९५

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) (बी) १६-(८)९५.—हिमाचल प्रदेश खण्ड रेविन्यू (ग्रामपंचमैट) ऐक्ट, १९८९ (१९८९ का १५) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख

20-12-95 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1989

(1989 का 15)

(राज्यपाल द्वारा 23 जून, 1989 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1989 है।

संक्षिप्त
नाम।

2. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 163 में,—

धारा 163
का संशोधन।

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में, “पांच सौ” और “एक हजार” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “एक हजार” और “दो हजार” शब्द रखे जाएंगे,

(ख) उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं (3), (4), (5) और (6) जोड़ी जाएंगी अर्थात् :—

“(3) जब हक या प्रतिकूल कब्जे के बारे में ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें अधिक्रमण द्वारा उस भूमि की वास्तविकता जिसमें इस धारा के अधीन बेदखली की गई है या की जानी है, तीस वर्ष से अधिक अवधि के कब्जे का दावा किया गया है, वहां माल अधिकारी जो ऐसिस्टेंट कुलैक्टर पहली श्रेणी की पंक्ति से नीचे का न हो प्रश्न को अवधारित करने की कार्यवाही करेगा मानो कि वह सिविल कोर्ट हो और ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो सिविल कोर्ट द्वारा प्रयोक्तव्य हैं।

(4) उप-धारा (3) के अधीन प्रश्न के अवधारण के लिए, माल अधिकारी उसी प्रक्रिया को अपनाएगा जो दीवानी न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचारण के लिए लागू है और वह निर्णय और डिक्री अभिलिखित करेगा जिसमें वे विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विनिर्दिष्ट की जानी अपेक्षित हैं।

(5) उप-धारा (4) के अधीन माल अधिकारी द्वारा दी गई डिक्री की अपील डिस्ट्रिक्ट जज को होगी मानो कि वह डिक्री मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री हो।

(6) उप-धारा (5) के अधीन अपील पर डिस्ट्रिक्ट जज की अपीलीय डिक्री पर एक और अपील उच्च न्यायालय में केवल तभी होगी यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि इसमें विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है।”

(ग) विद्यमान उप-धारा (3) की उप-धारा (7) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

धारा 171 3. मूल अधिनियम की धारा 171 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड का संशोधन। (25) को खण्ड (26) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(25) किसी भूमि की बाबत कोई प्रश्न या उस भूमि पर कोई अधिकार अथवा हक या उसमें हित जिस पर अधिकरण किया गया है वा जिसकी बाबत कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि यह उसमें निहित है या उसमें निहित समझी गई है और यह कि उसे धारा 163 की उप-धारा (1) के अर्जित उभरें बेदखल नहीं किया जा सकता है, और”।